Subsidy given to Food Corporation of India

+

*859. SHRI SURAJ BHAN:

SHRI RAM PRASAD AHIRWAR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to lay a statement showing:

(a) the amount of subsidy given to the Food Corporation of India during last three years (year-wise);

(b) what are the details of the distribution-incidentals of the Food Corporation of India during the same years and also the percentage of the acquisition cost of foodgrains;

(c) whether there is any proposal to progressively reduce this subsidy by improving the working of the Food Corporation of India; if so, how; and

(d) how do the distribution-incidentals of FCI and percentage of acquisition cost of foodgrain figures compare with those prevalent in private trade?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) the following amounts of subsidy have been given to the Food Corporation of India by the Central Government during the last three years:—

Year	Amount (Rs. in crores)
1979-80	600.00
1980-81	650.00
1981-82	700.00

(b) The distribution incidentals incurred by the Food Corporation of India during the last three years were as under:—

Distribution incidentals:

Year	Rate/Rs. per quintal of sales
1979-80	22.66
1980-81	29.05
1981-82 (RE)	32.05

Distribution incidentals as percentage to the acquisition cost:

1979-80	17%
1980-81	19%
1981-82 (RE)	18.5%

(c) The Corporation purchases and issues foodgrains at prices fixed by the Government. The issue prices do not cover the full costs incurred by the Corporation on procurement, movement, storage and distribution of foodgrains and are subsidised as a measure of deliberate social policy of the Government. The Corporation also carries buffer stocks of foodgrains on behalf of the Government and the carrying charges of buffer stocks are reimbursed to the Corporation. By their very nature, most of the expenses incurred towards procurement incidentals and distribution charges are either obligatory or unavoidable operational costs. The expenditure incurred by the Corporation in respect of the distribution operations over the last few years has been maintained between 17 per cent to 19 per cent of the acquisition cost.

The Corporation has, however, been constantly endeavouring to reduce its operational costs by undertaking various economy and efficiency measures. The norms for staffing the storage depots have been scaled down and new depots and new purchase centres are being manned by making internal adjustments. Efforts have also been made to improve, control

and minimise storage and transit losses. Special squads have been created for making surprise checks at the loading/unloading points and also at vulnerable points to ensure that not only the extant instructions and procedures are followed but storage and transit losses, malpractices/pilferages, etc., are also checked.

(b) The operational cost being incurred by private trade on foodgrains is not known to Government and as such it is not possible to compare the operational cost of Food Corporation of India with that of private trade.

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, यह जवाब मैंने पढ़ा है, इसमें मंत्री जी ने लिखा है कि यह खर्चा ज्यादा इसलिए होता है कि इसमें कुछ प्रोक्योर्मेन्ट चार्जेज हैं, कुछ स्टोरेज, डिसीट्रब्यूशन और हैण्डलिंग चार्जेज हैं लेकिन मैं समझता हूं इनके अलावा कुछ और चार्जेज हैं जोकि गलत हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल मदरास में चीनी खरीदी गई दहेली के लिये लेकिन दहेली में उसको ये ला नहीं सके.....

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह): किसने खरीदा?

श्री सूरज भान: गवर्नमेंट आफ इंडिया ने । मैं पूछ रहा हूं आप जवाब दे दीजिए। फिर उस चीनी में 20 लाख का घाटा उठाकर वहीं पर बेच दिया गया ।

दूसरी बात यह है कि यहां पर फ्लोर मिल्स हैं और यहां पर दिल्ली की मार्केट में गेहूं का आटा दो सौ रुपए क्वींटल से कम नहीं है लेकिन सरकार उनको 155 रुपए क्वींटल के भाव पर गेहूं दे रही है। यह सब्सीडी किस बात के लिए है? अगर कज्यूमर को सब्सीडी देकर आप घाटा उठायें तो बात समझ में आती है । लेकिन पब्लिक को नदेते हुए, इन मिल-मालिकों को देते हैं। मार्केट में दो सौ रुपये का रेट है, आप इनको 155 रुपये क्विंटल पर दे रहे हैं। क्या आप इसको बंद करेंगे? यह मेरा पहला क्वेश्चन है।

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Sir, it is our social obligation. The Food Corporation of India is functioning on behalf of Government of India. Before 1965, the Food Department, Government of India was handling the entire work. But, after 1965, Parliament had enacted a law under which the Corporation is doing the procurement work on behalf of Government of India. In addition to helping the farmers by giving them the price which have been fixed by Government, they have also been asked to distribute foodgrains at the issue price fixed by the Government. All this put together is the social obligation. The Corporation is doing the entire work. I cannot understand what the hon. Member is saying about sugar and all that. If he has got any idea about the purchase of sugar made by Government—whether it is more or less—let him give me a notice for that.

MR. SPEAKER: Mr. Minister, you have not replied to his question. Why are you supplying to the flour mills at fixed price and they are selling it at a higher rate?

SHRI R. V. SWAMINATHAN: That is also fixed. The flour mills cannot sell according to their whims and fancies. We supply them at certain prices and they have been asked to sell at a particular price.

SHRI SURAJ BHAN: Are they selling at a particular controlled rate? My question is by getting the foodgrains at subsidised rates, are they selling at least at the controlled rate?

RAO BIRENDRA SINGH: We control the prices of maida and suji. The resultant atta is allowed to be sold by the Mills.

आप क्या चाहते हैं? किस चीज पर कंट्रोल चाहते हैं। अपने तौर पर स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहें तो उनके साथ अण्डरस्टैंडिंग कर के कोई एग्रीमेंट कर के रिजलटेंट आटा टेक ओवर कर सकते हैं । यह दिल्ली में होता है, दिल्ली में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रिजलटेंट आटा ले कर पब्लिक डिस्ट्-

यूशन सिस्टम के जरिए से डिस्ट्रिब्यूट कर रहा है । मैदा की प्राइस हमें एक जगह पर रखनी पड़ती है क्योंकि जो ब्रेडस है ये बड़े मालदार लोगों के ही खाने की चीज नहीं है, इसको मजदूर भी खाते है। इसलिए उसकी प्राइस को कंट्रोल करना पड़ता है और इसके लिए मुनासिब है कि हम मुनासिब कीमत पर उन्हें आटा दें ।

श्री सुरज भान: अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहा है--

"The operational cost being incurred by private trade on foodgrains is not known to Government and as such it is not possible to compare operational cost of Food Corporation of India with that of private trade".

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लास्ट क्वेश्चन का जवाब दिया है और कहा है कि इनके चार्जिज बीस परसेंट है । 1979-80 में 17 परसेंट, 1980-81 में इन्हें 17 फीसदी ज्यादा खर्च करना पड़ा जो कि 19 परसेंट हो गये । 1981-82 में इनका 18.5 परसेंट एस्टीमेटिड है जो कि ज्यादा होगा और यह बीस परसेंट तक पहुंच गया होगा ।

मैं अम्बाला से आता हूं । मैंने वहां की मार्किट के एक ट्रेडर से पूछा है । उसने बताया कि 2 से 3 परसेंट कमीशन खर्च पड़ता है और मैक्सिमम 5 परसेंट तक कमीशन जाता है । सरकार का 20 परसेंट तक क्यों पहुंचता है ? क्या आप इसको कम करने की कोशिश करेंगे ताकि गरीब आदमियों पर इसका बोझा न पड़े और गरीब आदमियों को राहत मिले ? आपके प्राइवेट ट्रेडर मैक्सिमम पांच परसेंट पर काम चला सकते हैं तो आप क्यों नहीं चला सकते हैं ?

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Sir, the private traders have got their own ways. We cannot understand how they procure and how they sell, But, according to our information, their expenditure is more than ours. Therefore, we cannot compare with the private traders.

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, सिक्सथ फाइव ईयर प्लान जो बनाया गया, उसमें आपने एक बात रखी थी। वह यह रखी थी कि--

'The Planning Commission has urged that a significant reduction in the amount of subsidy is essential for the implementation of the Sixth Plan'.

फूड कारपोरेशन आफ इंडिया का जब आपने उत्तर दिया तो यह बताया कि आपकी सबसीडी बराबर बढ़ रही । मेहरबानी कर के यह बताइये कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया में ओवर स्टाफिंग कितना है, पिलफेज कितना होता है, लासेस कितने होते हैं और औवरहेड एक्सपेंडीचर कितना है ?

यह आप कृपा करके बताइए और जब आपने उत्तर दे दिया कि:--

"The operational cost being incurred by private trade on foodgrains is not known to Government and as such it is not possible to compare the operational cost of Food Corporation of India with that of the private trade."

आप यह भी नहीं मालूम कर सकते ? मिक्स इकानामी का मतलब यह नहीं था कि आप मालूम ही न करें कि प्राइवेट ट्रेडर्स का खर्चा कम क्यों होता है, आपका खर्चा अधिक क्यों होता है। सरकार सब्सिडी देती जाएगी और 700 करोड़ रुपया हर साल बढ़ता जाएगा, इसका उत्तर मेहरबानी करके दीजिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह: गवर्नमेंट आफ इन्डिया कंज्यूमर को ठीक भाव पर अनाज देने के लिए सबसिडी दे रही है । कंज्यूमर का इंटरेस्ट हमने देखना है। अगर प्राइवेट ट्रेडर्स का खर्चा हमसे कम होता तो प्राइवेट ट्रेडर्स जो भाव लेते हैं अनाज का इतना ज्यादा भाव क्यों होता? उनका खर्चा कम नहीं है, यह इस बात से साबित होता है कि जनता रिजीम में 1977-78 में यह एक्सरसाइज किया गया कि प्राइवेट ट्रेडर्स से पूछा जाए कि एफ सी आई की जगह वे क्या लेंगे और संभाल लें, इसके लिए वे क्या लेंगे और

उस वक्त प्राइवेट ट्रेडर्स ने सरकार को जो कोटेशन दिया वह फूड कारपोरेशन के खर्चे से ज्यादा था । इसलिए यही मुनासिब समझा गया कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया ही ठीक तरह से यह कार्य कर सकता है, अनाज के व्यापार को हैंडिल कर सकता है । आपके जनता रिजीम में दो बार सोचा गया, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ट्रेड रेप्रजेंटिव्स को बुलाकर पूछा कि आप किस तरह से हैंडिल करेंगे, चार्जेज क्या लेंगे, उन्होंने फूड कारपोरेशन से ज्यादा बतलाए ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मंत्री जी ने बताया कि मैदा कंट्रोल रेट पर इसलिए दिया जाता है कि उससे ब्रेड बनती है, जिसे आम आदमी खाता है । क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि गेहूं का आटा उससे भी नीचे तबके के लोग गांवों में खाते हैं, इसलिए जो गेहूं मिल वालों को दिया जाता है, उस आटे का कंट्रोल सरकार क्यों नहीं कर सकती ।

अध्यक्ष महोदय: जवाब दे दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन ये उनको निर्देश क्यों नहीं देते ? उनकी मर्जी पर क्यों छोड़ दिया गया है ।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जैसा कि इन्होंने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम को राज्य सहायता के रूप में 79-80 में 600 करोड़ रुपया दिया गया, 80-81 में 650 करोड़ रुपया दिया गया और 81-82 में 700 करोड़ रुपया दिया गया । उसी तरह से इन्होंने कहा कि वितरण संबंधी खर्चे में भी 79-80 में 22.66 रुपये प्रति क्विंटल, 80-81 में 29.05 रुपये प्रति क्विंटल और 81-82 में 32.05 रुपये प्रति क्विंटल खर्चा हुआ । कहने का मतलब यह है कि हर साल इनका खर्चा बढ़ता जाता है । उन्होंने बताया है कि--

"Efforts have also been made to improve, control and minimise storage and transit losses. Special squads have been created for making surprise checks at the loading/unloading points..."

इसलिए इसका दाम कम किया जा सकता था । एक तरफ तो इन्होंने यह बताया है कि विभिन्न तरीके अपनाए गए, जिससे खर्चा कम हो सके, दाम घट सके, इसके बावजूद आप देखेंगे कि रोज-रोज खर्चा बढ़ता जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि दाम बढ़ने के बावजूद आप यह कह सकते हैं कि दाम बढ़ने से रोकने के लिए व्यवस्था की गई है, आपकी व्यवस्था का क्या असर हो रहा है और पहले जो मैंने आटे के बारे में कहा, उसका भी उत्तर देने की कृपा करें ।

राव बीरेन्द्र सिंह : चार्जिज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि घट रहे हैं । जो बढ़े हैं वे इसलिए कि प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ती रही है और किसान के हाथ में कीमत वक्तन फवक्तन ज्यादा जाती रही है । आपका अगर यह सजेशन है कि कंज्यूमर को उसी भाव से मंहगा अनाज दिया जाए जैसे डागा जी का सजेशन था जो एक तरह से यह था कि सबसिडी नहीं होनी चाहिये और कंज्यूमर को कास्ट प्रइस पर ही दिया जाना चाहिये, तो वह मर जाएगा और हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं । यह एक सोशल आब्लीगेशन है पुअर मासिस को फीड करने की । जितना खर्चा फूड कारपोरेशन का होता है इसमें ज्यादा तर मंडी के चार्जिज हैं, हडलिंग चार्जिज हैं, मंडी के टैक्स हैं ट्रांन्सपोर्ट चार्जिज हैं या स्टोरेज चार्जिज हैं । 15-20 मिलियन टन अनाज अगर हर वक्त रखना पड़े तो कितना स्टोरेज के ऊपर, देखभाल के ऊपर ट्रांस्पोटेशन के ऊपर खर्च आता है इसका अंदाजा आप लगा लें । यह प्राइवेट ट्रेड के बस की बात नहीं है कि हिमाचल के इंटीरियर में दस हजार फूट की ऊंचाई वाले गांव तक इस भाव पर पहुंचा दे । सारे भारत में एक भाव पर कंज्यूमर के लिए हम अनाज तकसीम करना चाहते हैं । यह एक एसेंशियल कमोडिटी है । चालीस रुपए के करीब एक क्विंटल पर सबसिडी है । इस चालीस रुपये में सिर्फ दो रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज फूड कारपोरेशन का है । बाकी खर्चा ट्रांस्पोर्टेशन का, स्टोरेज का, इंटरेस्ट आन कैपिटल कुछ लास के ऊपर है । लास भी हम कम करने की कोशिश

कर रहे हैं । खर्च कम करने की कोशिश कर रहे हैं । जितना स्टाफ हमारे पास है उसी का इस्तेमाल करके जितना एक्सपैंशन हो रहा है, जितना ज्यादा अनाज हैंडल कर रहे हैं वह उतने ही स्टाफ से कर रहे हैं और इस तरह से वह खर्चा घट रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की कास्ट घट रही है । स्टोरेज के ऊपर प्रोक्योरमेंट से ले कर डिस्ट्रीब्यूशन तक हमारा इरादा यह है कि फूड कारपोरेशन को एक परसेंट के करीब लास के ऊपर चला सकें, सारे सिस्टम को चला सकें । दुनिया के किसी भी मुल्क के अन्दर कम से कम अंदाजा लास का यह है । इसमें ट्रांस्पोर्टेशन लास भी आ गया, स्टोरेज में जो होता है वह भी आ गया, खराबियां भी आ गईं, पिलफेज भी आ गया, सब चीजें आ गईं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आटे पर कंट्रोल के बारे में नहीं बताया है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : बता तो दिया है पहले ।

Development of Agro-industries under Sixth Plan

*860. SHRI MOHAMMAD ASRAR AHMAD: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the plan under consideration for the development of Agro-industries during the Sixth Plan period specially in U.P.; and

(b) the main features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

As a part of the overall strategy for development of agriculture, the Ministry of Agriculture is taking a number of steps for setting up of agro-industries in the country as a whole, and in .U.P. in particular during the 6th Five Year Plan. Some of the major programmes in this direction are given below:

I. Agro-industries in the country as a whole:

(i) Participation in State Agro-Industries Corporation in 17 States.

(ii) Fruit and Vegetable agro industries complexes in Bihar and Karnataka at a cost of Rs. 4.72 crores.

(iii) Fruit and Vegetable Development Corporation at a cost of Rs. 2 crores.

(iv) Fruit Juice Bottling Plant at Delhi at a cost of Rs. 1.2 crores.

(v) North Eastern Agricultural Marketing Corporation with a share capital of Rs. 5 crores.

(vi) Augmentation of capacity of production of sugar from 6 million tonnes in 1979-80 to 8 million tonnes in 1984-85.

(vii) Setting up of 43 sugar factories, 14 spinning mills, 5 soyabean processing units and 245 other agricultural procesing units in the cooperative sector.

(viii) In the cooperative sector through operation flood II five new dairies with a total capacity of 4.2 lakh litres daily are under construction and 12 dairies with a total capacity of 8.4 lakh litres daily are under planning. Twenty six dairies are being expanded.

(ix) Oilseed processing plants with capacity of crushing 15.46 lakh tonnes of oilseeds and with investment of Rs. 59.68 crores will be installed through the National Dairy Development Board.

II. Agro-industries in U.P.

(i) U.P. State Agro-industries Corporation.

(ii) Establishment of 7 new sugar factories and substantial expansion of 5 existing sugar factories.

(iii) Setting up of 5 modern rice mills, five dal mills, one soyabean processing unit, one oil mill complex and one cooperative spinning mill and rehabilita-